THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An amount of Rs. 8025.65 crores, is outstanding, as on 30.9.1996, of the Central Power Sector Undertakings against State Electricity Boards/State Governments. Government has, in principle, approved the proposal of the Ministry of Power to re-appropriate the outstanding dues of the Central Power Sector Undertakings upto September, 1996 from the Central Plan Assistance to the States. It has also been decided that future supply of power by the Central Power Sector Undertakings will be against advance payents or irrevocable letters of credit.

गुजरात में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं

129. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार और यूनीसेफ की सहायता से शहरी बुनियादी सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सेवाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) 1996-97 के दौरान अहमदाबाद, गोधरा, सूरत एवं भरूच जिलों में कितने क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अधीन लाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है इस पर होने वाले व्यय में केन्द्र तथा राज्य 60 : 40 के अनुपात में सहभागी हैं। योजना का लक्ष्य विकास क्रियाकलापों में स्लग निवासियों का प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने और सामाजिक सेवाओं की अनुकूल व्यवस्था, पर्यावरणीय सुधार तथा विशेषज्ञ विभागों के आय अर्जित करने वाले कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए स्लमों में प्रतिवास विकास समितियों को प्रोत्साहित करना है। पांच चुने हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जो शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम योजना का कार्यान्वियन जारी रखने के लिए आवश्यक हैं, यथा प्रशिक्षण क्षमता विकास, प्रबंध क्षमता विकास, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्रचार एवं प्रसार तथा अंत: क्षेत्रीय सम्पर्क, इनके लिए यूनीसेफ की सहायता उपलब्ध है।

(ग) कस्बे/क्षेत्र का चयन राज्य सरकार का दायित्व है। इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

Funds for Kothagundem Thermal Power Station

130. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the PRIME MINISER be pleased to state:

(a) whether Government have received any request from the Andhra Pradesh Government for release of funds for the works on stage V of Kothagundem thermal power station;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government to release the funds at any early date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Andhra Pradesh State Electricity Board (APSEB) have requested Power Finance Corporation (PFC) for a term loan assistance of Rs. 500 crores for completion of Stage V (2x250 MW) Units 9 & 10 Kothagundem Thermal Power Station.

(c) PFC have sanctioned a loan of Rs. 130 crores in August, 1996 to APSEB towards completion of balance works in respect of Unit 9, programmed to be synchronised by March, 1997.

Appropriation of dues of SEBs

131. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Ministry of power has sought the approval of Central Government for appropriation of 10,000 crore worth dues of SEBs to Central power PSUs;

(b) if so, the details of arrears outstanding against each of the SEBs to the Ministry of Power; and